भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1852

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

'अमृत' योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में परियोजनाएँ

†1852. श्री नवसकनी के.:

श्री सी. एन. अन्नादुरईः

श्री जी. सेल्वमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तमिलनाडु ने अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत 13,339.43 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 445 परियोजनाएँ शुरू की हैं और इनके कार्यान्वयन में निरंतर प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं का जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और शहरी परिवहन के क्षेत्रवार वितरण सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में 'अमृत' योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी केंद्रीय सहायता जारी की गई है;

(घ) पूर्ण हो चुकी, कार्यान्वयनाधीन और निविदा या अनुमोदन के विभिन्न चरणों में वर्तमान परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ङ) अमृत 2.0 के अंतर्गत तमिलनाडु में शहरी अवसंरचना विकास में और अधिक सहायता प्रदान करने एवं उसके सुदृढीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और तमिलनाडु में शहरी निवासियों को बेहतर सेवाप्रदाय सुनिश्चित करने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): जैसा कि तमिलनाडु राज्य द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) पोर्टल पर बताया गया है, राज्य द्वारा 28 शहरों/कस्बों में अमृत के तहत 13,339.43 करोड़ रुपये की 445 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 12864.69 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे किए जा चुके हैं।

जलापूर्ति क्षेत्र में, राज्य ने 7,436.02 करोड़ रुपये की लागत वाली 18 परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें से 7,330.96 करोड़ रुपये के भौतिक कार्य पूरे किए जा चुके हैं; सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में, 5,670.80 करोड़ रुपये की लागत की 18 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 5,301.12 करोड़ रुपये के भौतिक कार्य पूरे किए जा चुके हैं; पार्क तथा हरित क्षेत्र में, 232.61 करोड़ रुपये की लागत की सभी 409 परियोजनाएँ पूरी कि जा चुकी हैं।

परियोजनाओं के लिए 4,756.58 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता के सापेक्ष, अमृत के अंतर्गत 4,626.24 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ङ) अमृत 2.0 को 01 अक्टूबर, 2021 को तमिलनाडु राज्य सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरु किया गया है। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक रूपरेखा के भीतर परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता और कार्यान्वयन करने का अधिकार है। तमिलनाडु राज्य में अमृत 2.0 के तहत अब तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 14,687.83 करोड़ रुपये (संचालन और रखरखाव लागत सहित) की कुल 1,270 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है, जिसमें 7,721.59 करोड़ रुपये की 201 जलापूर्ति परियोजनाएं, 6,623.40 करोड़ रुपये की 30 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 229.19 करोड़ रुपये की 474 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं और 113.65 करोड़ रुपये की 565 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

(च) मिशन के दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान हैं। शहरी विकास और आवासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मिशन के दिशानिर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति मिशन की आवधिक

समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत 2.0 के तहत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। साथ ही, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है। परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने और निगरानी के लिए एक समर्पित अमृत 2.0 ऑनलाइन पोर्टल है।

*****